

एलपीजी की काला बाजारी करने वालों के लाइसेंस निरस्त करें- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलैक्टरों को दिशा निर्देश दिए

जयपुर, 28 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलैक्टरों को प्रतिदिन एलपीजी के संबंध में समीक्षा करके जमीनी परिस्थितियों का फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कालाबाजारी एवं ओवरप्राइसिंग में मिलत

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि शिकायतों का 24 घंटे में त्वरित समाधान किया जाए तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर मुख्य सचिव स्तर पर रिपोर्ट की जाए।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में एलपीजी आपूर्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

संस्थाओं या व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस निरस्तकरण की कार्रवाई एवं बार-बार उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण कर अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई तथा स्टैंक रजिस्टर एवं वास्तविक भंडारण का मिलान भी सुनिश्चित किया जाए।

शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में एलपीजी आपूर्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त टीम बनाकर विशेष अभियान चलाने तथा सभी जिलों में एलपीजी और आवश्यक वस्तुओं के

गोदामों, एजेंसियों एवं वितरण केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों का 24 घंटे में त्वरित समाधान हो तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर मुख्य सचिव स्तर पर रिपोर्ट दी जाए। इसी के साथ, सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। उल्लेखनीय है कि

राज्य सरकार द्वारा आमजन को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14435, 112 और 181 संचालित किए जा रहे हैं।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, संबंधित विभाग के अधिकारी एवं जिला कलैक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े।

‘तलाक के मामले में विदेशी कोर्ट के फैसले मान्य नहीं’

नई दिल्ली, 28 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें विदेशी तलाक के फैसलों पर कानूनी स्थिति साफ की गई है, खासकर उन मामलों में, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि किसी विदेशी कोर्ट द्वारा ऐसे आधार पर दिया गया तलाक, जिसे भारतीय कानून मान्यता नहीं देता, भारत में वैध या बाध्यकारी नहीं माना जा सकता।

इसके साथ ही, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी

■ **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह व्यवस्था खासतौर से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के लिए है।**

विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक जोड़े को अंतिम तलाक दे दिया, यह देखते हुए कि वे लगभग 18 सालों से अलग रह रहे थे।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। यह विवाद भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई एक शादी से जुड़ा था, जो बाद में अमेरिका और भारत, दोनों जगहों पर तलाक की समानांतर कार्यवाही का विषय बन गया।

इज़रायल का ईरान के एटमी ठिकानों पर बड़ा हमला

इज़रायल ने 50 फाइटर जैट के साथ ईरान पर बड़ी एयरस्ट्राइक की

■ **जवाब में ईरान ने यूएई, ओमान, कुवैत सऊदी अरब व बहरीन पर मिसाइलों से हमला किया।**

तेहरान, 28 मार्च। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को एक महीना हो चुका है, लेकिन खाड़ी देशों में हमले अब भी जारी हैं। आज सुबह तक अलग-अलग देशों से हमलों और इंटरसेप्शन की खबरें सामने आई हैं। ईरान-इज़रायल जंग के 28 दिन बाद अब हूती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए हैं। उधर, इज़रायल ने ईरान में बड़े स्तर पर एयरस्ट्राइक की है।

जानकारी के अनुसार, इज़रायल ने ईरान के अंदर 50 फाइटर जेट्स से हमला किया। इज़रायली सेना के मुताबिक, शुक्रवार रात ईरान के तीन इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना ने बताया कि ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए और कई घंटों तक चले। हमलों में अराक और जेस जैसे अहम इलाके शामिल थे। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें हथियार बनाने वाली सैन्य इंडस्ट्री और बैलिस्टिक के साथ एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री शामिल थीं।

उधर, ईरान ने आज यूएई, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब और

इस युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, चार हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4,000 टॉमहॉक मिसाइलें थीं। अगर यह सही है तो टॉमहॉक मिसाइलों का करीब एक चौथाई हिस्सा खत्म हो चुका है। इक्ष मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता बढ़ गई है।

बहरीन पर हमला किया। यूएई में अबू धाबी और दुबई के बीच स्थित खलीफा इकोनॉमिक जोन के पास इंटरसेप्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से तीन जगह आग लग गई। इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। बहरीन में ईरान की ओर से निशाना बनाए गए एक ठिकाने पर लगी आग को सिविल डिफेंस ने बुझा दिया। वहीं, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। साथ ही, पिछले 24 घंटों में नेशनल गार्ड ने 6 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले, ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर शुक्रवार रात को 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे। इस हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्र.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमत जताई, ताकि वैश्विक व्यापार और आपूर्ति शृंखला बाधित न हो।

प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय संप्रदाय के कल्याण केलिए क्राउन प्रिंस के निरंतर सहयोग के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

‘हूती विद्रोही यमन को जंग में झोंक रहे हैं’

सना, 28 मार्च। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यमन की सरकार ने हूती विद्रोहियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार का कहना है कि हूती आंदोलन देश को अनावश्यक युद्धों में धकेल रहा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, हूती लड़ाके ईरान के समर्थन में काम कर रहे हैं और क्षेत्रीय संघर्ष को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यमन सरकार ने इसे देश की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है।

इससे पहले दिन में खबर सामने आई थी कि हूती विद्रोहियों ने इज़रायल की ओर मिसाइल दागी, जिसे बीच रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़

■ **यमन सरकार ने आरोप लगाया कि हूती लड़ाके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं।**

गया है।

हूती विद्रोही यमन का एक सशस्त्र समूह है, जो लंबे समय से सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और देश के कई हिस्सों पर नियंत्रण बनाए हुए है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें ईरान समर्थित समूह के रूप में देखा जाता है।

यमन सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दे और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए।

‘दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की पहचान कदापि उजागर ना करें’

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया

■ **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेशों में ऐसा कुछ न लिखा जाए जिससे पीड़िता या उसके परिवार की पहचान उजागर हो।**

नई दिल्ली, 28 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए, इसे सबसे कड़े शब्दों में निंदनीय बताया है। शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोर्ट के आदेशों में पीड़िता या उसके परिवार की पहचान किसी भी रूप में सामने न आए।

न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि 2018 के निपुण सक्सेना बनाम यूनिन ऑफ इंडिया फैसले में स्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद निचली अदालतों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसके पीछे अदालतों की उदासीनता और इस तरह

किया गया था कि किसी भी माध्यम (फ्रिट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया) में पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद निचली अदालतों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसके पीछे अदालतों की उदासीनता और इस तरह

के अपराधों से जुड़े सामाजिक कलंक के प्रति जागरूकता की कमी को जिम्मेदार बताया गया। अदालत ने बताया कि 1983 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर धारा 228 जोड़ी गई थी, जिसका उद्देश्य दुष्कर्म पीड़िताओं की पहचान को सार्वजनिक होने से रोकना है। इससे

पहले ऐसा कोई स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध नहीं था, जिससे पीड़िताओं को सामाजिक बहिष्कार और मानसिक आघात का सामना करना पड़ता था।

पीठ ने अपने आदेश की प्रति सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि इस कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह टिप्पणी उस दौरान आई, जब अदालत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले की समीक्षा कर रही थी, जिसमें नौ साल की बच्चों से दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया गया था।

‘भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भी जोर दे रही है कि एनडीए के छोटे सहयोगी दल, जैसे एलजेपी (राम विलास), एचएमए (सेक्युलर) और आरएलएम को भी नए मुख्यमंत्री के चयन में पूरी तरह भरसे में लिया जाए।

जदयू के सूत्रों ने कहा कि अगर पार्टी को गठबंधन में छोटे भागीदार की भूमिका निभाने को कहा गया, तो वह

विधानसभा अध्यक्ष पद पर दावा करेगी। एक जदयू सूत्र ने कहा, “किसी को यह नहीं लाना चाहिए कि कुमाय के राज्यसभा जाने से जदयू कमजोर हो गई है। कुमाय अब बिहार को और ज्यादा समय देंगे। इस बीच, भाजपा के बरिष्ठ नेता विनोद तावडे इस समय पटना में हैं और कुमर के संभावित उत्तराधिकारी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। राज्य भाजपा नेता जदयू के रुख पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में ऑफिस फैसला भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व ही करेगा। भाजपा खेमे को उम्मीद है कि एनडीए के सभी सहयोगियों की सहमति से सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो जायेगा।

अयोध्या राजघाट पर यज्ञशाला में लगी आग पंडाल जलकर राख हुआ

चूँकि नौ दिवसीय महायज्ञ समाप्त हो चुका था और पंडाल में कोई नहीं था इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई

अयोध्या, 28 मार्च। अयोध्या के राजघाट स्थित बाटी बाबा आश्रम के पास महालक्ष्मी नारायण यज्ञशाला में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय हुई, जब नौ दिवसीय महायज्ञ का समापन हो चुका था, और यज्ञशाला खाली हो गई थी।

गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की वजह से लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। अगर इतनी भीषण थी कि एक एकड़ में फैला यज्ञ स्थल कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। जहां यह भीषण आग लगी, वही स्थान राम मंदिर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह

■ **हादसा राजघाट के बाटी बाबा आश्रम के पास स्थित महालक्ष्मी नारायण यज्ञशाला में हुआ, जहां 20 मिनट से 28 मार्च तक नौ दिवसीय महायज्ञ आयोजित हुआ था। घटनास्थल से राम मंदिर मात्र 800 मीटर दूर है।**

महायज्ञ 20 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कर रहे हैं। सुबह लगभग 11:30 बजे पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हो गया था और श्रद्धालु वहां से जा चुके थे।

इसी दौरान, अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत मौके

वॉशिंगटन की राजनीति में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अयोग्य है। यदि इसे चुनौती दी जाती है, तो मामला कांग्रेस के पास जाता है, जहां इस निर्णय को बरकरार रखने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत जरूरी होता है।

ऐतिहासिक रूप से, इस प्रावधान का कभी भी किसी राष्ट्रपति को उसकी इच्छा के विरुद्ध हटाने के लिए पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए इसका उल्लेख भी अपने आप में भारी राजनीतिक महत्व रखता है। यह केवल नेतृत्व को लेकर चिंता का ही संकेत नहीं देता, बल्कि सत्ता तंत्र के भीतर विस्थापन के संकेत का संकेत भी देता है।

इस मांग का समर्थन भी खास महत्व रखता है। यह ऐसे समय में सामने आई है, जब ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट आई है, ईंधन की बढ़ती कीमतों के आर्थिक प्रभाव को लेकर जनता में चिंता बढ़ रही है, और ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को संभालने के प्रशासन के तरीके पर संदेह गहरा रहा है। हालिया सर्वेक्षणों में ट्रंप की लोकप्रियता 30 प्रतिशत से कम गिरती दिखाई गई है, जहां आर्थिक प्रबंधन और महंगाई असंतोष

के प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं। इस पृष्ठभूमि में, 25वें संशोधन का उल्लेख एक संवैधानिक तर्क से अधिक एक राजनीतिक संदेश जैसा प्रतीत होता है, मानो वर्तमान स्थिति को सामान्य नीतिगत मतभेद के बजाय, संस्थागत संकट के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही हो।

उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के लिए यह सुझाव बेहद संवेदनशील स्थिति पैदा करता है। संवैधानिक रूप से, धारा 4 को लागू करने के किसी भी प्रयास में वे केन्द्रीय भूमिका में हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से, वे ट्रंप के जनदेश और उनके मतदाता आधार से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे किसी कदम या उसकी संभावना भर से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है, जहां ट्रंप का अभी भी काफी प्रभाव है।

वास्तव में, 25वें संशोधन को लागू करने में व्यावहारिक बाधाएं भी बहुत बढ़ी हैं। इसके लिए न केवल वेंस की सहमति, बल्कि मंत्रिमंडल के बहुमत का समर्थन भी आवश्यक होगा, और इनमें से कई सदस्य राष्ट्रपति के करीबी माने जाते हैं। यदि ऐसा निर्णय

ईरान ने अमेरिका के 6 युद्ध पोतों पर मिसाइल दागी

तेहरान, 28 मार्च। ईरान के सशस्त्र बलों ने अमेरिका के छह सामरिक जहाजों को निशाना बनाया है तथा दावा किया गया है कि इस हमले में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों और क़द्र 380 क्रूज मिसाइलों का उपयोग किया। इस्तामिक रिवालयशाही गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के जनसंपर्क कार्यालय ने शुक्रवार देर रात जारी बयान में यह जानकारी दी।

ईरान के इस्तामिक रिवालयशाही गार्ड कॉर्प्स से संबद्ध अर्ध-सैन्यीक यूज एजेंसी तसनीम की रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत, ईरानी बलों का 84वें हमला है। आईआरजीसी की नौसेना ने अल-शुबैख बंदरगाह और दुबई के समुद्र तटों और बंदरगाह पर अमेरिकी-इज़रायली सेना के खिलाफ सटीक हमले किए। हमले में अमेरिकी सैनिक मारे गए।

हरियाणा में आतंकी साजिश का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

हरियाणा पुलिस ने सिरसा से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस थानों की रैकी कर रहे थे

सिरसा, 28 मार्च। महिला थाना ब्लास्ट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दी। पुलिस ने पांच संदिग्धों को काबू किया है, जो पुलिस चौकी और थानों की रैकी कर, उनके वीडियो दुबई में बैठे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से सम्पर्क में थे।

पुलिस जांच में सामने आया है कि संदिग्ध एक मीडिएटर के जरिए गैंगस्टर के संपर्क में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कथित विस्फोटक सामग्री का इंतजार कर रहे थे, जिसकी डिलीवरी 30 मार्च को होने की आशंका थी। शुक्रवार रात पुलिस ने चौरी की मोटोसाइकिल पर सवार राजबीर उर्फ

■ **आरोपी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की साजिश में शामिल थे और दुबई में बैठे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से सम्पर्क में थे।**

राजीव उर्फ डीसी, उसके जौजा और एक नाबालिग को पकड़ा।

राजबीर के मोबाइल से सिरसा की हुडा पुलिस चौकी और सिविल लाइन थाना की रैकी के वीडियो बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने हांसी निवासी रोहित उर्फ काकू को भी काबू किया, जो

हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। रोहित से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मिलकर कुछ दिन पहले रेकी कर पीठों में मिलकर कुछ दिन पहले रेकी करके बनाया था। थाना भर चला सचें आपरेशन पुलिस ने सेक्टर-19 स्थित प्लैटों में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक विशेष सर्च अभियान चलाया। संदिग्ध के स्वजनों का कहना है कि पुलिस ने सादी वर्दी में तलाशी ली और घंटों में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में ली। संदिग्ध नाबालिग की मां ने बताया कि वह अपने बेटे को पुलिस के पास पूछताछ के लिए छोड़कर आई थी।

प्र.मंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया

■ **प्र.मंत्री मोदी ने कहा, उन्हें इस परियोजना के शिलान्यास व उद्घाटन का अवसर मिला जो उनके लिए विशेष गौरव की बात है।**

नोएडा, 28 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर एयरपोर्ट) के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विमान रखरखाव, परम्पत्त और ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा का भी शिलान्यास किया।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के नई उड़ान देने वाला प्रयास है। विकसित भारत के संकल्प के तहत आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और उत्तर प्रदेश अलग देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों करने का अवसर मिला, जो उनके लिए विशेष गौरव का विषय है। उन्होंने इसे जनता को समर्पित

करते हुए कहा कि यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का नया इंजन बनेगा और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर सहित पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट किसानों, लघु एवं मध्यम उद्योगों और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा। यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ-साथ क्षेत्रीय उड़ानों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। यह परियोजना विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का प्रतीक बनेगी।